सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आवास का आवंटन

2520. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास के आवंटन के लिये सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों आदि से प्राप्त हुए कितने आवेदन शहरी विकास मंत्रालय में कब से लम्बित पड़े हुये हैं और पिछली बार ऐसा आवंटन कब किया गया था ;

(ख) अब तक ऐसे आवंटन किस आधार पर किये गये हैं और ये आवंटन जिन प्राधिकारियों की सिफारिशों पर किये गये, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों को आवंटन उनके दल संबंधों के कारण नहीं किये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा लेखकों जैसे राष्ट्रीय महत्व के उपयोगी कार्य में कार्यरत व्यक्तियों को आवंटन के लिये सामान्य पूल आवास का विशेष कोटा उद्दिष्ट किया गया है । इन व्यक्तियों को आवंटन संबंधित मंत्रालयों की सिफारिश पर किया गया जाता है अर्थात् सामाजिक कार्यकर्ताओं को आवंटन समाज कल्याण विभाग द्वारा संबंधित मंत्री के अनुमोदन से की गई सिफारिश पर किया जाता है ।

जहां तक राजनैतिक कार्यकर्ताओं का संबंध है, उनके मामलों में आवंटन के लिये कोई विशेष कोटा उद्दिष्ट नहीं किया गया है । तथापि, स्वतंत्रता सैनानियों को आवंटन गृह मंत्रालय द्वारा गृह मंत्री के अनुमोदन से की गई सिफारिश पर किया जाता है ।

इन मामलों में लम्बित पड़े आवंदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या
1. सामाजिक कार्यकर्ता	15
2. विविध श्रेणी अर्थात् राष्ट्रीय महत्व के कार्य में कार्यरत व्यक्ति, जैसे कि लेखक आदि	6
3. स्वतन्त्रता सेनानी	29

इन श्रेणियों में अंतिम आवंटन 29-2-88 को स्वीकृत किया गया है ।

धारावाहिकों में हिन्दी शब्दों और वाक्यों का विकृत किया जाना

2521. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को हाल ही में एक सांसद का इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे धारावाहिकों में हिन्दी शब्दों और वाक्यों को विकृत करने का कार्य सतत् रूप से चल रहा है और तथ्यों को भी हास्यास्पद ढंग से विकृत किया गया और गलत ढंग से पेश किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की गलती अंग्रेजी कार्यक्रमों में नहीं की जाती है ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० के० एस० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । किसी भी भाषा के कार्यक्रम में अशुद्धियां हो सकती हैं ।

(ग) दूरदर्शन ने प्रायोजित धारावाहिकों के बाहरी निर्माताओं तथा दूरदर्शन के निर्माताओं को भी अनुदेश जारी किए हैं कि वे अपने द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की भाषा में अशुद्धियां न करें ।

चीनी का उत्पादन

2522. **श्री रशीद मसूद :**
श्री अजीत सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1988 के दूसरे पखवाड़े में चीनी का उत्पादन गत वर्ष की उसी अवधि में हुए उत्पादन से अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान नीति में कोई विशेष परिवर्तन करने का विचार रखती है ताकि गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को चीनी के अधिक उत्पादन का लाभ मिल सके और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जनवरी, 1988 के दूसरे पखवाड़े के दौरान 8.60 लाख मीटरी टन चीनी की उत्पादन हुआ था जबकि 1987 का तदनुरूपी अवधि के दौरान 8.53 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था ।

(ख) चूंकि पिराई मौसम अभी केवल मध्य में ही है, इसलिए पखवाड़े के उत्पादन के आधार पर मौसम के दौरान कुल उत्पादन के निश्चित आंकड़ों का हिसाब लगाना कठिन है ।

(ग) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करना सरकार की नीति है । अधिक उत्पादन का अभिप्राय होगा गन्ना उत्पादकों को फसल का अधिक इस्तेमाल करना और उपभोक्ता को आसानी के साथ चीनी उपलब्ध करना । गन्ना उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी उपलब्ध करना सरकार की नीति के मूल घटक हैं । वर्तमान चीनी नीति में परिवर्तन करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है ।

Indian Labour force in Arabian Countries

2523. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state;

(a; whiether it is a fact that the demand f°r Indian labour in Arabian countries is going up after a set back in the previous year; and

(b) if so, what is the total estimate of the Indian labour force working in the Arabian countries and the facilities provided by the Government of India, though its embassies, for absorbing them in those countries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) and (b). Yes, Sir. About 9 lakh Indians are working in Arabian countries. Emigrants go for employment for a fixed period. The question of their absorption does not arise.

Policy for increasing food grains production

2524. SHRl V. NARAYANASAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Govern- ment have formulated a policy to cover 14 States to increase the agricultural production for the year 1988-89 and 1989 90 by way of intensive cultivation; and

(b) if so, what is the total amount of money proposed to be spent by Government for each selected district to increase